BUSINESS STANDARD HINDI N.D 07/01/2020

`निर्विक' से मिलेगा देश के निर्यात को दम

दिलाशा सेठ और शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 6 जनवरी

सरकार निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए अगले कुछ हफ्तों में निर्यात वित्त योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत छोटे कारोबारियों को रुपये और डॉलर के लिहाज से कम ब्याज दर की पेशकश की जाएगी और उनके लिए प्रीमियम की लागत भी कम होगी।

मंत्रिमंडल में पेश प्रस्ताव के मुताबिक निर्विक (निर्यात ऋण विकास योजना) योजना के तहत निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज की दर गिरकर डॉलर के लिहाज से 3.15 फीसदी और रुपये के लिहाज से 7.35 फीसदी रहने की संभावना है। अभी क्रेडिट पर ब्याज दरें विदेशी मुद्रा में तीन फीसदी से छह फीस और रुपये के लिहाज से करीब 10 फीसदी है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'मंत्रिमंडल में निर्विक योजना पर अगले एक या दो हफ्ते में विचार किया जाएगा। इसके तहत निर्यातकों को क्रेडिट पर प्रतिस्पर्द्धी ब्याज दरें मुहैया की जाएंगी।'

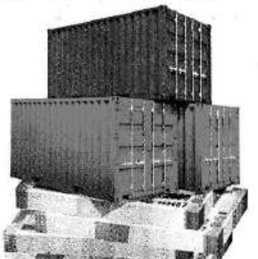

...निर्यात पर जोर

- निर्यात में गिरावट रोकने की कवायद में जुटी सरकार
- कम ब्याज दर और प्रीमियम लागत की पेशकश
- मंत्रिमंडल अगले कुछ दिनों में कर सकता है विचार
- बैंकों को निर्यात क्रेडिट पर ऊंची बीमा कवरेज

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के आंकड़ों के मुताबिक निर्यात क्रेडिट में विदेशी मुद्रा की हिस्सेदारी करीब 53 फीसदी और रुपये की 47 फीसदी है। अधिकारी ने कहा, 'अब कारोबारी सीधे विदेशी मुद्राओं में निर्यात क्रेडिट ले सकते हैं, इसलिए मंत्रालय कुल निर्यात क्रेडिट में विदेशी मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है।'

संशोधित निर्यात क्रेडिट बीमा योजना (ईसीआईएस) में भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) के माध्यम से बैंकों को निर्यात क्रेडिट पर ऊंची बीमा कवरेज देकर निर्यात दरों को कम करने का लक्ष्य है। यह ब्याज अधिकतम दो तिमाही या ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित होने तक कवर किया जाएगा। अगर 90 दिन तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को (एनपीए) घोषित कर दिया जाता है। इस योजना निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर निर्यात क्रेडिट बीमा कवर का भी विस्तार करेगी जिससे निर्यात क्रेडिट पर कम ब्याज दरों में मदद मिलेगी।

इसके अलावा 80 करोड़ रुपये तक के खातों पर प्रीमियम की वार्षिक दर 0.6 फीसदी तक लाई जाएगी जबकि 80 करोड़ रुपये से अधिक के खातों पर इसे घटाकर 0.72 फीसदी किया जाएगा।

ईसीजीसी के अधिकारियों का कहना है कि वे तब तक बैंक के दस्तावेज और रिकॉर्ड नहीं खंगालेंगे जब तक ऋण पर नुकसान 10 करोड़ रुपये न पहुंच जाए। पहले यह सीमा एक करोड़ रुपये थी।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

`निर्विक' से मिलेगा देश के निर्यात को दम

पृष्ठ 1 का शेष

नवंबर में निर्यात में 0.32 फीसदी की गिरावट दर्ष की गई। इस तरह निर्यात में लगातार चौथे महीने और इस वित्त वर्ष में पांचवें महीने गिरावट आई।

फियो के महानिदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अजय सहाय ने कहा, 'निर्यात क्रेडिट की दरों में कमी से निर्यात क्षेत्र को बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे निर्यातकों को बेहतर ब्याज दरों के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी और व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी। इससे निर्यात चक्र या परिचालन चक्र की लागत में कमी आएगी। जो निर्यातक एक महीने में दो निर्यातक चक्र करते थे, वे अब तीन कर पाएंगे।'

ईसीआईएस में दावों के त्वरित निपटान की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए 30 दिन के भीतर 50 फीसदी अस्थायी भुगतान किया जाएगा। सहाय ने कहा कि निर्यात के लिए कम ब्याज दरों के अलावा निर्यातकों को बेहतर रेटिंग से भी फायदा मिलेगा क्योंकि ईसीआईएस को निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाने पर विचार किया जा सकता है।

बैंकों को उम्मीद है कि इससे बैंक निर्यातकों को ऋण देने में दिलचस्पी दिखाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि ईसीजीसी का लक्ष्य सालाना 3 लाख करोड़ रुपये कवरेज का है जो वित्त वर्ष के अंत तक कवरेज से बाहर थे। अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए सरकार ईसीजीसी को सालाना 1,700 करोड़ रुपये देगी। वाणिज्य विभाग ने साफ किया है कि ईसीजीसी के दायरे में न केवल ऋण का मूलधन आएगा बल्कि चुकाया नहीं गया ब्याज भी आएगा।